MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Non-payment of salaries to workers of tractors and tools division of HMT (Pinjore)

कुमारी शैलजा (हरियाणा): सर, हरियाणा में एच0एम0टी0 की दो यूनिट्स हैं। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि माननीय लीडर ऑफ दि हाउस और माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, यू0पी0ए0 सरकार में एच0एम0टी0 यूनिट के रिवाइवल के लिए हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज दिया गया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहां के हजारों एम्प्लॉइज़ को 19 महीने से और 11 महीने से वेतन का एक भी पैसा नहीं मिला है। सर, यह इतने अफसोस की बात है। वे लोग बेचारे कहां जाएं? उनके पास अपने बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, सामाजिक कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं, राशन तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सर, ये बेचारे हजारों एम्प्लॉइज़ यहां से कहां जाएं? अब इनका अगर पैकेज सोच रहे हैं तो आपने वी0आर0एस0 की स्कीम बनाई है। वी0आर0एस0 में आपने बाकी सारे एच0एम0टी0 यूनिट्स को लिया है लेकिन पिंजोर की जो दो एच0एम0टी0 यूनिट्स हैं, उनको इस वी0आर0एस0 स्कीम से बाहर रखा है। सर, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यहां पर इतनी अच्छी मशीनरी है, उन्होंने पहले डिफेंस के लिए काम किया है, रेलवे के लिए काम किया है, मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं। तो क्यों नहीं रेलवे के साथ या डिफेंस के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं? यहां पर उम्दा मशीनरी तैयार करने वाले लोग इसमें बड़े टेलेंटेड लोग हैं। वे यहां इतने सालों से लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं सरकार वहां पर "मेक इन इंडिया" की मिसाल पेश करती है? एक तरफ "मेक इन इंडिया" का नारा देते हैं और दूसरी ओर हमारे बने बनाए यूनिट्स जिनको तैयार होने में वर्षों लग गए हैं तथा जिनका इतना योगदान रहा है देश की इण्डस्ट्री में, उसको ये क्यों बंद करने पर तुले हुए हैं? सर, बेचारे वहां के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। सर, वहां पर सैंकड़ों एकड़ वेल्युएबल जमीन है। हमको शक है कि कहीं यह जमीन रिअल स्टेट वालों को न बेच दें। यह इतना वेल-कनेक्टेड एरिया है, रेलवे से भी, एयरपोर्ट से भी, रोड से भी, यह इतना बढ़िया एरिया है। उसके पास में इण्डस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहां के हिमाचल का, जो एक मेजर हब हो सकता है, लेकिन उसका ये खत्म करना चाहते हैं। "मेक इन इण्डिया" का नारा खोखला है। हमारे हजारों एम्प्लॉइज़ बेचारे आज भूख के कगार पर हैं, उनके बच्चे भी भूख के कगार पर हैं। इनको उनकी कोई चिंता नहीं है। सर, इन बेचारे एम्प्लॉइज़ का क्या होगा, मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहती हूं। मैंने इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। केवल एक्नालेजमेंट आया है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। क्या इस सरकार की इस बारे में कोई जवाबदेही नहीं बनती है वहां के लोगों के प्रति?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with what the hon. Member has said. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with what the hon. Member has said. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सर, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया (राजस्थान): महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश)ः सर, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार)ः सर, मैं भी इसको एसोसिएट करता हूं।

श्रीमती रेणुका चौधरीः सर, मैं भी इसका समर्थन करती हूं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, this is nothing, but deception of the people. *...(Interruptions)...* You cannot carry on by not paying the workers continuously for 2-3 years. *...(Interruptions)...* This is the scenario in most of the public sector undertakings. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. So, you associate yourself with it. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the Government must respond to it. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiwari, under what rule is your point of order, tell me? *...(Interruptions)...* Okay; it is on record. *...(Interruptions)...*

Under what rule is your point of order? *...(Interruptions)...* Under what rule is your point of order? *...(Interruptions)...* Under what rule is your point of order? *...(Interruptions)...*

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): Sir, let me address you at least. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. *...(Interruptions)...*

KUMARI SELJA: Sir, the Minister is replying. *...(Interruptions)...*

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He is responding, Sir. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to respond to that?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ANANT GEETE): Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; do that.

श्री अनंत गीतेः उपसभापति महोदय, सदन की सदस्या शैलजा जी ने एचएमटी, पिंजौर की युनिट को लेकर यहां पर जो प्रश्न उपस्थित किया है, मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी के फेवर के लिए या किसी को लैंड बेचने के लिए कोई षड़यंत्र नहीं है।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार)ः लैंड की बोली लग रही है। **...(व्यवधान)...**

श्री अनंत गीतेः कोई षड़यंत्र नहीं है, किसी को बेचने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हमने इसके पहले एचएमटी के तीन युनिट्स बंद करने का निर्णय लिया। अब एचएमटी, पिंजौर भी संकट में है, लगभग ड़ेढ़ साल से अधिक समय से हम उनका वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, वह पूरा घाटे में है। इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि जिस तरह से एचएमटी के तीन युनिट्स को हमने अच्छा वीआरएस पैकेज दिया, उसी तरह से हम एचएमटी, पिंजौर को भी वीआरएस का पैकेज देने वाले हैं। वहां के कर्मचारी इससे संतुष्ट हैं, उनसे मेरी चर्चा हो चुकी है।

कुमारी शैलजाः आप उन बेचारों को तनख्वाह तो दीजिए। वे लोग भूखे मर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Tiwari. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: We want clarity on Telangana HMT. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: It is not merely HMT; a number of public sector undertakings. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different issue. ...*(Interruptions)*... For that, you give another notice.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Workers are not getting their wages. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For that, you give another notice. ...*(Interruptions)*... Mr. Tapan, you can give another notice. ...*(Interruptions)*... Now, Mr. Tiwari, under what rule is your point of order? Under what rule?

SHRI PRAMOD TIWARI: Mr. Deputy Chairman, Sir, the House is run by rules. The House is run by the Constitution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are encroaching on the time of the Members who have given Zero Hour notice. So, tell me quickly.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, if you do not permit me,.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have permitted you. Under what rule? Tell me the rule.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, let me say something. The House is run by....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No general statement. Tell me the rule number.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, please read Rule 267 again. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि विजय माल्या जब 10,000 करोड़ रुपए लेकर चला गया तो इन्होंने एक lookout notice जारी किया कि वह जहां भी immigration में मिले, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन क्योंकि इन्हीं के टिकट पर, इन्हीं के समर्थन से वह जीतकर आया था, इन्होंने अपने lookout notice को कैंसिल किया और यह कहा कि सिर्फ सूचित कर दिया जाए, जिसका फायदा उठाकर विजय माल्या 10 हज़ार करोड़ का आरोपी, देश छोड़कर भाग गया। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think this issue has already been discussed here. Now, listen. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारीः मैं सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि विजय माल्या **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji; this issue was raised here, discussed here.

श्री प्रमोद तिवारीः उसका बयान छपा है, उसने बहुत साफ और **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I myself have given the ruling that it should be referred to the Ethics Committee; so, nothing more.

श्री प्रमोद तिवारीः कि वह लौटकर भारत में जाने का इरादा नहीं रखता है। **...(व्यवधान)...** मैं इस सरकार पर इल्ज़ाम लगाता हूं कि **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down, sit down. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Ali Anwar Ansari. ...*(Interruptions)*... Shri Ali Anwar Ansari. ...*(Interruptions)*... This was already raised here, discussed here. ...*(Interruptions)*... I have given the ruling that it should be referred to the Ethics Committee. ...*(Interruptions)*... That is the final matter. Sit down. ...*(Interruptions)*... For the rest, law will take its own course. ...*(Interruptions)*... Yes, Ansariji ...*(Interruptions)*...

Non-implementation of reservation policy in institutions of higher education in the country

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार)ः महोदय, देश में उच्च शिक्षा में ओबीसी को 27 परसेंट रिज़र्वेशन का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... Only what Shri Ali Anwar Ansari says will go on record. Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अली अनवर अंसारीः लेकिन तमाम विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान ओबीसी रिज़र्वेशन को लागू नहीं कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**